



नस्लवाद बनाम पुलिस प्रशासन: चुनौतियां एवं चिंतन— अमेरिका के संदर्भ में

डा. अर्चना शर्मा

उपप्राचार्या , वेदान्ता स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रींगस, सीकर, राजस्थान

मेरा स्वपन है कि भविष्य का अमेरिका ऐसा हो जहां मेरे बच्चे अपने रंग से नहीं बल्कि अपने काम और चरित्र से पहचाने जाएं— मार्टिन लूथर किंग

4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता तो मिल गई परन्तु अफ्रीका से लाए गये अश्वेत गुलामों को दासता से मुक्ति नहीं मिली। आजादी के बाद उन्हें अधिकार देने के मामले पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका में मतभेद थे। 1861 से 1865 के बीच चले गृहयुद्ध द्वारा अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त कराया, पर 100 साल बाद भी अमेरिकी समाज में अश्वेतों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया। श्वेत वर्ग द्वारा उनसे घरेलू कार्य, खेती, मजूदरी, कराई जाती थी, यहां तक कि उनका शारीरिक शोषण भी होता था। उन्हें श्वेतों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। 1955 से लेकर 1968 तक मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। **सिविल राइट्स मूवमेंट** नामक अहिंसक आंदोलन अश्वेतों को समानता, न्याय, दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था, इसमें लाखों लोग शामिल हुए। इस आंदोलन ने अश्वेतों को जागरूक किया। 1968 में श्वेत कट्टरपंथी जेम्स अर्ल रे द्वारा मार्टिन लूथर की हत्या कर दी गई। वे व्हाइट सुप्रीमसी की सोच से प्रभावित थे। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देने के खिलाफ थे। हत्या के मुकदमें में यद्यपि उन्हें 99 साल की कैद की सजा सुनाई गई, 1998 में जेल



में ही उनकी मृत्यु हो गई, पर आज भी अमेरिका में रंगभेद, श्वेत-अश्वेतों के मध्य असमानता की विचारधारा जिंदा है।

सामयिक घटनाक्रम- 25 मई 2020 को अमेरिका में एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें एक पुलिस कार के पास एक अश्वेत नागरिक फ्लॉयड जमीन पर मुह के बल गिरा, उसकी गर्दन एक पुलिस अधिकारी के घुटनों के नीचे दबी हुई थी और दो पुलिस अधिकारी उसे दबोचे हुए थे। डेरेक शौबिन नामक पुलिस अधिकारी ने फ्लॉयड को अपने घुटनों के नीचे दबा रखा था। दम घुटने से उसने अस्पताल जाते- जाते दम तोड़ दिया। डेरेक को गिरफ्तार कर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया गया, इस मामले से जुड़े चारों पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर हत्या का आरोप लगाया गया। लेकिन अफ्रीकी-अमेरिकी समुदाय का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ। सालों से उनके सीने में दबी भेदभाव की आग शोला बनकर उभर रही है। न्याय मांगने उतरे लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है आखिर अफ्रीकी-अमेरिकन नागरिकों के साथ बेरहमी कब रुकेगी। मिलियापोलिस –सेंटपॉल, अटलांटा, न्यूयार्क, लॉस एजिल्स, मियामी, डेट्रॉइट, सीएटल, वाशिंगटन डीसी, सहित अमेरिका के अनेकों शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आये। कई शहरों के मेयर जो अश्वेत हैं, उन्होंने यह जोर देकर कहा कि इसमें असली मुद्दा पुलिस बर्बरता और अश्वेता के प्रति दुर्व्यवहार से जुड़ा है। कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत भी हो गई। अमेरिका के मिलियापोलिस शहर के सेंटपॉल से आरंभ हुआ यह घटनाक्रम फ्लॉयड की मौत के समाचार से पूरे अमेरिका में नस्लवादी भेदभाव और पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ प्रदर्शन और दंगे भड़क उठे। आगजनी, तोड़फोड़, हिंसक आंदोलन, प्रदर्शन, लूटपाट की घटनाएं गोलियां चलना और पुलिस स्टेशन को आग लगाना, जैसी घटनाओं के



बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आग में घी डालने जैसा था। यह विरोध और प्रदर्शन न केवल अमेरिका के अनेक शहरों में बल्कि विश्व के अनेक देशों में फैल गया। इस घटना में पुलिस तंत्र का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस महकमे को जनता और संविधान का संरक्षक और कानून व्यवस्था स्थापित करने वाला प्रशासनिक तंत्र माना जाता है। अमेरिका के मिनेसोटा के मिलियापॉलिस शहर में पुलिस जार्ज फ्लॉयड के पास काले धन की जानकारी लेने जब उसकी घर पहुंची तो उसने सहयोग नहीं किया। सोशल मीडिया पर 8मिनट 46 सैकण्ड के वीडियो में पुलिस की हैवानियत सामने आई। उसमें पुलिस ने हथकड़ी लगा रखी थी और उसकी गर्दन पर पैर रखा हुआ था। इस दुर्दान्तक घटना की विश्व स्तर पर निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन की प्रमुख मिशेल बेचलेट ने इस निर्मम हत्या के पीछे नस्लीय भेदभाव का कारण बताया। भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि पुलिस कितनी निर्दयता से काले लोगों को दबाकर रखती है और प्रशासन उनकी मदद की गुहार को अनसुना करता है, यह दर्दनाक घटना है। इस घटना ने एक बार फिर से अश्वेत लोगों के प्रति जारी भेदभाव और नस्लीय हिंसा का विवाद उत्पन्न कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप का विवादास्पद बयान भी चर्चा में रहा। जिसमें उन्होंने कहा कि लूट शुरू होती है तो शूट भी शुरू होती है। उन्होंने स्थानीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि स्थिति नहीं संभल रही थी तो नेशनल होमगार्ड भेजे जाने चाहिये थे, जबकि स्थानीय मेयर जेकब फ्रे ने कहा हिंसा और लूटपाट को किसी भी स्थिति में बर्दास्त नहीं किया जायेगा। अमेरिका में सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, और अश्वेतों के गुस्से की वजह सिर्फ पुलिस की हैवानियत नहीं है बल्कि इसका संबंध अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिकों के साथ सालों से हो रहे भेदभाव से भी है। आज भी अश्वेतों के साथ दोगुना दर्जे



का व्यवहार किया जाता है। अब लोग इंसाफ के लिए आर-पार के आंदोलन पर उतर आये है। पूरे अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ हिंसा का भयंकर तांडव जिसमें ओरेगॉन में हफ्तों तक प्रदर्शन चला। सिएटल में मार्च निकाल रहे लोगों के साथ पुलिस की हिंसक झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों ने डिटेंशन सेंटर को आग लगा दी। टैक्सॉस के रिचमण्ड में पुलिस ने केमिकल स्प्रे डालकर भीड़ को रोका। कोलोराडो के ऑरोरा में लोगो ने हाइवे को जाम कर दिया। कंटुकी में ऐसे ही दृश्य देखे गये। पोर्टलैण्ड में घटना के साठ दिन बाद तक भी प्रदर्शनकारियों ने धरने दिये, जिसमें पूर्व सैनिको ने भी उनका साथ दिया। ट्रंप ने स्थिति काबू करने के लिए फ्रेडरल एजेंट की नियुक्ति की, इन्होंने लोगों के साथ मारपीट की, इससे प्रदर्शनकारी और भडक उठे।

अमेरिका का संविधान सभी नागरिकों को चाहे व श्वेत हो या अश्वेत, समान अधिकार देता है। प्रशासन और राजनीति भी खुले तौर पर रंगभेद नीति का समर्थन नहीं करती है। अश्वेत नागरिक प्रशासन, विधायिका, न्याय, शिक्षा, प्रबन्ध और नीति निर्धारक जैसे पदों पर कार्यरत् है। अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा 2009 से 2017 तक कार्यरत रहे। ओबामा और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडन और उच्च पदाधिकारी भी इस तथ्य को स्वीकारते है कि अमेरिका में अश्वेत नागरिकों के प्रति भेदभाव व पुलिस बर्बरता का दौर अभी थमा नहीं है। ओबामा के समर्थकों में यद्यपि श्वेत नागरिकों, महिलाओं और युवाओं का एक बडा वर्ग है। यद्यपि अमेरिका में 19वीं शताब्दी में दासता का युग अब्राहम लिंकन के शासन काल में समाप्त हो गया था। वे रिपब्लिकन पार्टी के थे। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी विचारधारा से जुडे है, पर उनकी विचारधारा अश्वेत विरोधी एवं व्हाइट सुप्रीमेसी की समर्थक है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इस घटनाक्रम पर दिये गये बयान



का मिनियापोलिस की कांग्रेस प्रतिनिधि इल्हान ओमार ने हिंसा भडकाने वाला बयान बताया है। इल्हान सोमालिया के शरणार्थियों के समाज से निकली युवा डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि है जो हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव चुन कर आई है।

नागरिक अधिकार अधिनियम— अमेरिका में 1964 तक गोरे और काले लोगों के बीच अधिकारिक तौर पर भेदभाव था। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाया गया। इसके तहत रोजगार प्रथाओं और सार्वजनिक स्थानों पर जाति, रंग, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया। 1965 में मतदान के अधिकार को पुनःस्थापित और संरक्षित किया। 1965 के अधिनियम द्वारा आव्रजन और राष्ट्रीयता सेवा कानून बनाकर इस भेदभाव को समाप्त किया गया परन्तु वास्तविकता यह है कि अधिनियम बनने के बावजूद भी श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों पर किये जा रहे भीषण अत्याचार जारी रहे। 1965 में न्यायालय ने एक आदेश द्वारा स्कूलों के लिए यह नियम बनाया कि श्वेत और अश्वेत वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे पर श्वेत वर्ग द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया। 60 के दशक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में नागरिक अधिकारों के लिए एक जन आंदोलन चलाया गया उस समय फ्लोरिडा में पुलिस अधिकार वॉल्टर हेडली ने 1967 में नगर शांति बहाल करने के लिए “**व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स—शूटिंग स्टार्ट्स**” जैसे जुमले का प्रयोग किया गया। नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं द्वारा इस जुमले का जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसे रंगभेद और नस्लवाद से जोड़कर देखा गया। इसी प्रकार वर्तमान में ट्रंप द्वारा दिये गये बयान का मिनियापोलिस की कांग्रेस प्रतिनिधि इल्हान ओमार “**डेमोक्रेटिक पार्टी**” ने हिंसा भडकाने वाला बयान बताकर विरोध किया। इसी प्रकार जार्ज फ्लॉयड के मुंह से निकला वाक्य “**आई कैंट ब्रीथ**” यानी मैं सांस



नहीं ले पा रहा हूँ। रंगवाद और नस्लवाद की प्रतीक बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका— अफ्रीकी नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 से 1968 में नस्लीय भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने से संबंधित थे। इनमें दक्षिण में अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966—1976 तक चला। नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य निष्पक्षता, समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, राजनैतिक और आर्थिक अधिकार, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, श्वेत अमेरिकनों द्वारा उत्पीडन से मुक्ति और नस्लीय भेदभाव का अंत आदि थे। इन संघर्षों में एनएएसीपी, एसएनसीसी सीओआरई, एसएलएलसी आदि जैसे संगठनों से सक्रिय भूमिका निभाई। 1968 में फेयर हाउसिंग अधिनियम के तहत घरों की बिक्री या किराये पर देना जैसे भेदभाव के आधार को प्रतिबंधित किया गया। अनेक ऐसे अधिनियम पारित किये गये जिनका संबंध रंगभेद और नस्लभेद की समस्या से था। इनमें— ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड 1954, रोजा पार्क्स और मोंटगोमरी बस बहिष्कार 1955—56, लिटिल रॉक में वर्ण भेद समाप्ति 1957, सिट—इंस 1960, फ्रीडम राइड्स 1961, मतदाता पंजीकरण आयोजन, मिसिसिपी विश्वविद्यालयों का एकीकरण 1956—1965, अलबनी आंदोलन 1961—1962, बर्मिंघम आंदोलन 1963—1964, वांशिगटन पर मार्च 1963, सेंट ऑगस्टाइन फ्लोरिडा 1963—1964, मिसिसिपी फ्रीडम समर 1964, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964, मिसिसिपी फ्रीडम डेमोक्रेटिक पार्टी 1964, सेलमा और मतदान अधिकार अधिनियम आदि हैं। 1965 दशकों से अश्वेतों के प्रति अत्याचार से लड़ने के लिए **ब्लैक लाइव्स मैटर** नामक संस्था का जन्म हुआ। यह अश्वेतों के प्रति ज्यादातर करने वाले श्वेत नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के विरोध में प्रदर्शन आयोजित कर उन्हें न्याय दिलवाने का कार्य करती है, जो पुलिस अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं। फरवरी 2012 में निहत्थे अश्वेत ट्रेवॉन मार्टिन की हत्या के आरोपी जार्ज जिमरमैन को एक साल बाद न्यायिक हिरासत से बरी



कर दिया गया । 2014 में फेंरगुसन में माइकल ब्राउन और न्यूयार्क में एरिक गार्नर की मौत पुलिस द्वारा अन्याय और दबोचे जाने के कारण हुई, तब गार्नर ने भी यही गुहार लगाई थी कि मेरा दम घुट रहा है। 2015 में बाल्टी मोर मैरीलैंड में फ्रेडी ग्रे की हत्या की विरोध में हिंसक दंगे भडके थे। अमेरिका में 1955 से 1968 तक नागरिक अधिकार आंदोलन के द्वारा अफ्रीकी-अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करते हुए दक्षिणी देशों में मतदान अधिकार को पुनर्स्थापित किया गया। इसमें गोरे अमेरिकन द्वारा उत्पीडन से मुक्ति और तस्लीम भेदभाव को समाप्त कर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना उन्हें राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान करना था। ट्रंप शासन काल में अश्वेत नागरिकों के प्रति भेदभाव के कई उदाहरण मिलते हैं यह भी सत्य है कि पुलिस ज्यादतियों के शिकार लोगों में अश्वेतों की संख्या अधिक है। 60 के दशक पूर्व भी पुलिस प्रशासन अश्वेतों के प्रति हो रहे अत्याचारों को नजर अंदाज करता था और अमेरिकन पुलिस श्वेत वर्ग की संरक्षक थी, ऐसी स्थिति वर्तमान में भी है।

श्वेत और अश्वेतों के बीच भेदभाव करती पुलिस

अमेरिका में हर पुलिसकर्मी को रंगभेद जैसी वारदात को पूरी तरह खत्म करने का प्रशिक्षण दिया जाता है पर अमेरिका की पुलिस समानता के व्यवहार की यह शपथ भूल जाते हैं। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिकों को लेकर श्वेत पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सवाल उठते रहे हैं। यद्यपि इनहें खारिज किया जाता रहा है इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं निरंतर जारी हैं। अमेरिकन समाचार पत्र “द गार्जियन” में कराए गये सर्वे के अनुसार अमेरिका में पुलिस द्वारा प्रति 10 लाख लोगों में मारे गये 7.13 लोग अश्वेत ही होते हैं। जबकि मारे गये श्वेतों की संख्या 2.91 है। अमेरिकी पुलिस द्वारा एक साल में एक हजार लोग मारे जाते हैं। अमेरिका



के अटार्नी जनरल विलियम बार ने मई 2020 में यह स्वीकार किया कि अश्वेत नागरिक जार्ज फ्लॉयड की हत्या में पुलिस का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहना पड रहा है कि हमारी पुलिस श्वेत और अश्वेतों के बीच भेदभाव करती है। यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों में भी यह धारणा है कि पुलिस प्रशासन एक ही मामले में श्वेत और अश्वेतों को अलग-अलग तरीको से डील करता है। अफ्रीकी-अमेरिकी वर्ग के मन में पुलिस द्वारा भेदभाव की बात बहुत गहरे तरीके से पैठ बना चुकी है। विलियम ने कहा कि रंगभेद या नस्लभेद जैसे आरोपों पर हमें जल्दी और समय रहते कमियों को दूर करने की आवश्यकता है और उचित कार्यवाही भी करनी होगी तथा कानूनी एजेंसियों की यह जिम्मेदारी है कि वो अफ्रीकी-अमेरिकी लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करे कि हर अमेरिकी के साथ एक जैसा वर्ताव किया जायेगा। विलियम का नस्लवाद या रंगभेद पर दिया हुआ यह बयान ट्रंप प्रशासन से बहुत भिन्न है। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो के अनुसार प्रशासन या पुलिस में नस्लवाद जैसी कोई चीज नहीं है। अमेरिका में न्यूयार्क के सिटी हॉल पर प्रदर्शनकारी पुलिस विभाग का बजट घटाने या पुलिस तंत्र को समाप्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गये। उन्होंने सरकार और राज्य के महापौर से पुलिस विभाग के बजट में करीब 7600 करोड घटाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में मैसाचुसेट्स के सीनेटर मिटरोमनी भी शामिल हुए। शांति मार्च भी निकाला गया, मिनियोपोलिस नगर परिषद् पुलिस विभाग खत्म करने की अपील कर रहा है। परिषद् सदस्यों की सिटी पार्क में बैठक हुई इसमें यह कहा गया कि दशकों की कोशिशों के बावजूद ये साबित हो गया है कि पुलिस नहीं सुधर सकती अतः इस शहर में पुलिसिंग व्यवस्था खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। न्यूयार्क में मेयर बिल डेक्लासियों ने भी न्यूयार्क पुलिस की फंडिंग



खत्म कर शेष बची राशि सामाजिक कार्यों में लगाने की बात कही। न्यूयार्क पुलिस के 272 पुलिस अफसरों ने अश्वेत फ्लॉयड की मौत को लेकर इस्तीफा सौंप दिया, जो सन् 2019 की तुलना में 49 प्रतिशत ज्यादा है। अमेरिका में अश्वेतों पर अत्याचार, हिंसा के 90 प्रतिशत मामलों में पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमें ही नहीं चलते। मिनियोपोलिस शहर में जहां जार्ज फ्लायड मारा गया, वहां लंबे समय से पुलिस द्वारा अश्वेतों पर ज्यादातियां की जा रही थी। काफी समय से सक्रिय संगठनों द्वारा पुलिस नृशंसता और अत्याचारों के खिलाफ मुहिम चला रखी है, पर पुलिसकर्मियों को दंड न मिलने के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं। मैपिंग पुलिस वायोलेंस संगठन के अनुसार अमेरिका में 2013 से 2019 के बीच हत्याओं में शामिल 99 प्रतिशत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालतों में मामलें पेश ही नहीं होते, इन मामलों की जांच में भी ढील बरती जाती है। सुधारकों ने सिटी कौंसिल, राज्य विधानसभा में अपनी बात पहुंचाई, वे निरन्तर ये आग्रह करते रहे कि रंगभेद, आर्थिक असमानता और पुलिस के आक्रामक रवैये में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा किए गए शूटआउट्स में शामिल 98 प्रतिशत पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया गया, दो प्रतिशत पुलिसवालों के खिलाफ भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अमेरिका के बड़े शहरों रेनो, ओक्लाहोमा, अनाहाइम में ही पूरे अमेरिका के हत्या के मामलों से ज्यादा पुलिस द्वारा अश्वेतों के मारने के मामले दर्ज किए गए हैं। 10 में से 6 अमेरिकन यह मानते हैं कि पुलिस भी श्वेतों की तुलना में अश्वेतों के साथ ज्यादा बर्बरता करती है। मिनियोपोलिस शहर जहां यह घटना हुई, वहां की 20 प्रतिशत आबादी अश्वेत है। इनमें से करीब 9 फीसदी अश्वेत पुलिस में है, इसके बावजूद मिनियोपोलिस में पुलिस के अत्याचारों का सबसे अधिक शिकार अश्वेत ही है, वे श्वेतों की तुलना में सात



गुना ज्यादा अत्याचार झेलते हैं। नागरिक अधिकारों पर काम करने वाले वकील और डेमोक्रेसी फॉर कलर के संस्थापक स्टीव फिलिप कहते हैं जो कुछ हो रहा है वह ऐतिहासिक है, यह बड़े बदलाव की तैयारी है। न्यूयार्क टाइम्स के पोल वॉच के मुताबिक ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने बड़ी शीघ्रता से अमेरिकियों की सहानुभूति हासिल की है।

1960 के दशक के बाद से अमेरिका ज्यादा अशांति के दौर से गुजर रहा है। 25 मई 2020 को मिनीयोपोलिस में अश्वेत जार्ज फ्लॉयड की मौत के बाद 350 से भी अधिक शहरों में दंग भड़कें। अमेरिकियों ने अपने पुलिस बल को जनसेवक की बजाय हमलावर सेना के रूप में व्यवहार करते देखा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 1 जून 2020 को प्रकाशित लेख में लिखा कि लोगों ने पुलिस के तौर तरीकों में सुधार की दस साल से चली आ रही प्रक्रिया के विफल होने से हताशा जताई है। अमेरिका में नागरिकों के पास बड़ी संख्या में हथियार और बंदूक होने से पुलिस का काम करना कठिन हो जाता है। वर्ष 2000 से 2014 के बीच में ड्यूटी पर कार्यरत 2445 पुलिस अधिकारी मारे गये। हर साल पुलिस की गोली से लगभग 1000 व्यक्ति मारे जाते हैं। पुलिस के हाथों मरने वाले लोगों में श्वेतों की तुलना में अश्वेतों की संख्या तीन गुना अधिक है। युवा अश्वेतों की मौत का एक बड़ा कारण पुलिस हिंसा है। अश्वेतों को सजा मिलने की संभावना भी अधिक रहती है। समान अपराध होने पर भी उन्हें श्वेतों के मुकाबले ज्यादा सजा मिलती है। जेलों में 33 प्रतिशत कैदी अश्वेत हैं। सजायाफ्ता लोगों में व्यस्कों की आबादी के 13 प्रतिशत अश्वेत शामिल हैं। इस असमानता को अमेरिका की पुलिस सिस्टम में भेदभाव का सबूत माना जा सकता है। वहां पुलिस की ट्रेनिंग युद्ध लड़ने के समान होती है। नागरिकों की मौत के मामलों में बहुत कम पुलिस अधिकारियों को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ब्राउन विश्वविद्यालय



के समाजशास्त्री निकोल गोंजालेज वान क्लीव और अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन के वकील सोमिल त्रिवेदी ने एक अध्ययन में कहा प्रोसिक्यूटर्स के लिए पुलिस मामले तैयार करती है, बदले में उनका रुख पुलिस के प्रति नरम रहता है। बड़ी संख्या में अश्वेत अमेरिकी, अफ्रीकियों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अश्वेतों के लिए अलग नियम कानून होते है। अपराधिक न्याय का संपूर्ण तंत्र रंगभेदी है। पुलिस यूनियन अपने दोषी सदस्यों का समर्थन करती है। कई शहरो में पुलिस अधिकारियों को टकराव टालने व बल प्रयोग करने पर उसके लिए जिम्मेदार ठहराने के कदम उठाये पर आज जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे है, ऐसा 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद देखा गया। अश्वेत बहुल जिलों में अश्वेत नेता प्रदर्शनकारियों को समझा रहे है कि वे अपना नुकसान न करें। अश्वेतों पर अत्याचार की घटना ने अमेरिकियों की सोच बदल दी है। वर्ष 2015 के बाद 5 साल में ऐसा मानने वालों की संख्या 26 प्रतिशत बढ गई, जिसमें 71 प्रतिशत अश्वेत भी यह मानते है कि नस्लवाद, भेदभाव एक बड़ी समस्या है और पुलिस अत्याचारों के खिलाफ अमेरिकन इतिहास में अब तक इस विषय पर बड़ी सहमति बनी है। अमेरिका में बढते नस्लवाद और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ साहसिक कदम उठाते हुए खिलाडियों ने भी खेलों का बहिष्कार किया। उन्होनें कहा कि पुलिस की जबावदेहिता, कूरता, और अपराधिक न्याय के मुद्दों को हल करने के लिए सार्थक कदम उठाना अनिवार्य है। इसमें एनबीए, महिला एनबीए, मेजर लीग बेसबॉल और मेजर लीग सॉकर के खिलाडियों ने मोर्चा संभाला। एनबीसी में 75 प्रतिशत खिलाडी अफ्रीकन-अमेरिकन है। ब्लैक लाइव्स मॅटर मूवमेंट में भी खिलाडियों ने बढचढ कर हिस्सा लिया। खेलने से मना करने के कारण आयोजको को पांच बडे टूर्नामेंट मुकाबले टालने पडे।



पुलिस यूनियन का हस्तक्षेप एवं दबाव—

अमेरिका में पुलिसकर्मियों की यूनियन पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि यूनियन दोषी पुलिस अफसरों को बचाती है। पुलिस तंत्र के काम में सुधार के तरीकों का पूरी तरह विरोध करती है। फर्ग्यूसन, बाल्टीयोर और मिनियापोलिस में अश्वेतों की हत्याओं के बाद पुलिस के कामकाज में सुधार की मांग तेज हुई। वहीं पुलिस यूनियन परिवर्तनों की सबसे बड़ी विरोधी के रूप में हत्याओं, ज्यादतियों और गलत आचरण के आरोपी पुलिसकर्मियों का बचाव करती है। उनके जोर देने पर मामलों की सुनवाई बंद कमरों में होती है। पुलिस यूनियनों के अपने अभियान चलाने और सुधारों को रोकने के लिए याचिकाएं दायर करने जैसे कामों के लिए बहुत पैसा है। न्यूयार्क शहर की पुलिस यूनियन में 2014 के बाद राज्यों और स्थानीय अभियानों पर करीब 10 लाख डॉलर से भी अधिक खर्च किए। सेंटलुई में प्रोसीक्यूटर ऑफिस में पुलिस कदाचार की जांच के लिए अलग यूनिट बनाने के खिलाफ यूनियन ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। जांचकर्ताओं द्वारा अश्वेत जार्ज फ्लॉयड की हत्या के लिए एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने का मिनियापोलिस पुलिस यूनियन के प्रमुख बॉब क्राल ने विरोध किया। कुछ मामलों में पुलिस यूनियनों ने सुधारों का सीधे विरोध नहीं किया, पर व्यवहार में ऐसे मामलों पर अमल भी नहीं किया। क्लीवलैंड की यूनियनों ने केन्द्र सरकार के सुधारों को धीमी गति से किया है। बाल्टीमोर में जस्टिस विभाग ने पुलिस आचरण को बदलने के लिए प्रस्ताव रखा तो यूनियन ने अपनी समस्याएं सामने रख दी। बफेलो में एक यूनियन के प्रमुख ने कहा कि यूनियन उन दो पुलिस अधिकारियों के पूरी तरह साथ है जिन्हें एक बुजुर्ग को जमीन पर गिराने के लिए अभी हाल ही में निलंबित किया गया है। निलंबित अफसरों के समर्थन में 57 अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिये। शिकागो में एक 17 वर्षीय



हत्या के दोषी अफसर जेसनवान ड्राइक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। दरअसल यूनियन और सिटी कॉन्सिल के बीच समझौते के बाद लोगों ने चुप्पी साध ली। न्यूयार्क की पुलिस यूनियन सुधारों की सबसे मुखर विरोधी है। ब्रुकलिन में एक व्यक्ति के पुलिस अधिकारियों की गोली से मरने के बाद ब्लासियों को पुलिस विद्रोह का सामना करना पडा। शिकागो सहित कई पुलिस यूनियन अफसरों पर कार्यवाही रोकने के लिए समझौतों के हथियार का इस्तेमाल करती है। यूनियनों के पास पर्याप्त साधन रहते हैं और वे केन्द्र सरकार के प्रस्तावों में भी अडंगा लगाती है।

दशकों के जारी अश्वेतों के प्रति अत्याचारों का इतिहास

अश्वेतों के साथ भेदभाव का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, अमेरिका का इतिहास इस बात का गवाह है कि राजनीति और सामाजिक दृष्टि से अश्वेत नागरिकों के साथ भेदभाव चाहे वे (काले अफ्रीकी— अमेरिकी या भूरे एशियाई लातिनी) हो। व्हाइट हाउस की सुप्रीमेसी (श्वेत प्रभुत्व की भावना) जो 70 साल पुरानी क्लक्स, क्लान जैसी आतंकी संस्कृति से जुडी हुई हैं, वर्तमान में भी विद्यमान है। इसकी शुरुआत 1619 में उत्तरी अमेरिका से हुई थी। अश्वेतों के खिलाफ हिंसा अत्याचार, का निर्मम इतिहास घिनौना है। सन 1619 से 1865 तक अमेरिका में अफ्रीकी बंदी या तो गुलामों की तरह बेचे गये या युद्धबंदी के रूप में थे। अमेरिका के उपनिवेश मैसाच्युसेट्स में 1641 में गुलामी प्रथा को कानूनी जामा पहनाया गया। संवैधानिक परिवर्तन के द्वारा 1808 में अमेरिकी संसद ने अंतरराष्ट्रीय गुलाम व्यापार को प्रतिबंधित किया। अमेरिका में गुलामों को खरीदा बेचा जाता था और निर्मम अत्याचार होते थे। धीरे-धीरे इनकी स्थिति और अधिक बदतर होती गई। दास प्रथा का अंत 1863 में लिंकन द्वारा मुक्ति की उदघोषणा जारी कर किया गया। 1865 में अमेरिका के कुल 36 राज्यों में से



तीन चौथाई राज्यों ने गुलामी की प्रथा को खत्म करने संबंधी संविधान के 13वें संशोधन को मंजूरी दी, पर मिसिसिपी राज्य में 1995 में गुलामी खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 1866 के सिविल राइट एक्ट ने अमेरिकन अश्वेतों को सार्वजनिक सुविधाओं को बिना भेदभाव के प्रयोग की अनुमति दी, पर 1875 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। 1889 से 1922 के बीच अमेरिका में 3436 अश्वेतों को लिचिंग में मार डाला गया। 1918 से 1921 के बीच अमेरिका में 28 अफ्रीकी मूल के अमेरिकन नागरिकों को भीड़ ने जलाकर मार डाला। यद्यपि समय के साथ ऐसी घटनाएं कम होती गईं लेकिन पूरी तरीके से रूकी नहीं। अमेरिका में सदियों से अश्वेतों के गुलाम बनाया जाता था। मार्टिन लूथर किंग ने अपनी हत्या से पूर्व कहा था कि यदि दुनिया के अश्वेतों को गरीबी, अपमान और उपेक्षा से जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो संपूर्ण विश्व खतरे में पड़ जायेगा। 200 सालों की गुलामी के बाद अश्वेत अमेरिकियों को 1965 में कानूनी तौर पर समानता के अधिकार मिले लेकिन उन्हें आज भी सामाजिक सुरक्षा, कर्ज और शिक्षा जैसे मामलों में और जानबूझकर आर्थिक सुविधाओं से परे रखा गया। 2009 में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जब पदभार संभाला तब यह माना जा रहा था कि अश्वेतों के खिलाफ अत्याचार खत्म हो जायेंगे। 2014 में बराक ओबामा के शासन काल के दौरान अश्वेतों की मौत पर विरोध प्रदर्शन हुआ। 2015 में वाशिंगटन पोस्ट में पुलिस की ओर से फायरिंग में मारे गये 4400 मामले सामने आये। अश्वेत वर्ग की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 13.3 प्रतिशत है पर कुल मौतों का एक तिहाई हिस्सा अश्वेत नागरिकों का है, जबकि पुलिस शूट में मारे गये व्यक्तियों का प्रतिशत 23.4 है। स्टैटिस्टिका के आंकड़ों के अनुसार 2019 में पुलिस द्वारा फायरिंग में मारे गये 24 प्रतिशत अफ्रीकन-अमेरिकी थे। रिपोर्ट के अनुसार इन शूटआउट्स में शामिल



98 प्रतिशत पुलिस वालों के विरुद्ध कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। 2 प्रतिशत पुलिस वालों के खिलाफ भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अमेरिका के बड़े शहरों जैसे रेनो, ओक्लाहोमा, अनाहाइम, में पूरे अमेरिका की हत्या के मामलों से ज्यादा पुलिस द्वारा अश्वेतों के मारने के मामले दर्ज किये गये। अमेरिका में श्वेत वर्ग की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 60.4 प्रतिशत है जबकि पुलिस शूट में मारे गये व्यक्ति 36.8 प्रतिशत है।

अमेरिका में अश्वेत महिलाएं भी पुलिस हिंसा का शिकार होती हैं, फिर भी उनके पक्ष में संगठित आंदोलन नहीं होते हैं। अश्वेत महिलाओं को रंगभेद और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। इन पीड़ित महिलाओं की आवाज को शब्द देने के लिए 2015 में **हर कैम्पेन संगठन** गठित हुआ। यह अश्वेत महिलाओं पर अत्याचार और उनकी हत्याओं के मामलों को उठाता है। श्वेत महिलाओं का एक वर्ग करेन भीम, जो 2017 से रेडिड पर है, पिछले कुछ सप्ताह से इसमें श्वेत महिलाएं स्वयं को पीड़ित बताती हैं और अश्वेतों की शिकायतें पुलिस से करती हैं लेकिन अब इसने नया रूप धारण कर लिया है। इंटरनेट पर श्वेत महिलाओं द्वारा अश्वेतों और एशियाईयों के खिलाफ जो अभियान चला रखा था, उस पर हिंसक और आपत्तिजनक फुटेज की बाढ़ आ गई। करेन अब रंगभेद के शर्मनाक प्रदर्शन का ऑनलाइन मंच बन गया। कई बार महिलाओं ने अश्वेतों की शिकायत करते हुए पुलिस को बुलवाया, गुलामी के दौर पर श्वेत वर्ग के मालिक गुलाम लडकियों और महिलाओं से दुष्कर्म करते थे। श्वेत महिलाओं की अमेरिकी समाज में अच्छी और नैतिक छवि पेश की गई और श्वेत पुरुषों द्वारा इनकी रक्षा करना जरूरी बताया गया। इस तरह से अश्वेत पुरुषों पर हिंसा को जायज ठहराया गया। अमेरिकन संविधान में 19वें संशोधन द्वारा 36 राज्यों की सहमति के पश्चात् महिलाओं को वोट देने के अधिकार को संरक्षित किया गया पर इसमें अश्वेत



लेटिन एशिया या अफ्रीकी अमेरिकी महिला शामिल नहीं थी। ईडा बी वेल्स जैसी अश्वेत कार्यकर्ता ने भेदभाव और श्वेत नारीवादियों द्वारा उपेक्षाएं झेली। यह क्रम निरन्तर चला रहा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मताधिकार अधिनियम पर टिप्पणी के बाद भी अश्वेतों को निशाना बनाया जा रहा है। वर्ष 1920 के आसपास अश्वेत महिलाओं ने मत विधालय की स्थापना की। 100 साल पूर्व 19वां संविधान संशोधन लाते वक्त किसी ने यह नहीं सोचा था कि 2020 में अश्वेत महिला अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी, इस संघर्ष और बलिदान से अश्वेत महिलाओं को भी मतदान का अधिकार प्राप्त होगा।

आय एवं सम्पत्ति संबंधी असमानता—

अमेरिका में अश्वेतों की आय श्वेतों की तुलना में 40 प्रतिशत कम है एवं उनके पास सम्पत्ति का भी दस प्रतिशत ही है। कानूनी तौर पर इतने वर्षों पूर्व अधिकार मिलने के बावजूद भी उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में अधिक सुधार नहीं आया है। परिणाम यह निकला कि आज भी अश्वेत अमेरिकन परिवार श्वेत परिवारों से 40 प्रतिशत कम कमाते हैं। उनके पास सामान्य श्वेत परिवारों की तुलना में केवल 10 प्रतिशत सम्पत्ति है। सन् 1960 से लेकर 2010 के बीच अश्वेत पुरुषों और महिलाओं के जेल जाने की दर 3 गुना बढ़ी है। पिछले 50 सालों में अश्वेत वर्ग ने जो तरक्की की, उससे उन पर गोरे लोगों द्वारा लगाये गये अवसरों के बंधन टूटने लगे फिर भी सुनियोजित भेदभाव जारी रहा। अमेरिकन पुलिस के हाथों मरने वाले निहत्थे नागरिकों में अश्वेतों की संख्या अधिक है। असमानता और अपराधिक न्याय की व्यवस्था ने इस भेदभाव को और अधिक बढ़ाया है। 2001 में जन्में लगभग 3 में से एक अश्वेत को अपने जीवन काल में कभी न कभी जेल अवश्य जाना पडा, जबकि श्वेतों में 17 में से 1 व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। अश्वेत बहुल इलाकों में गरीबी का स्तर अधिक है।



अतः बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, जेल जाने, जल्दी मरने, बेरोजगार होने का प्रतिशत अधिक है। मार्टिन लूथर किंग के पत्र और दस्तावेजों का सम्पादन करने वाले इतिहासकार क्लेबोर्न कारसन के अनुसार रंगभेद की समस्या खत्म करने के लिए अवसरों के ढांचे में परिवर्तन जरूरी है। अश्वेतों में गरीबी दर अधिक होने के कारण इन्हे अलग बस्तियों में रहने को मजबूर होना पडा। 1970 में अमेरिकन शहरों में 93 प्रतिशत अश्वेत अलग बस्तियों में रहते थे। 2010 की जनगणना के अनुसार यह आंकडा 70 प्रतिशत था। जोनिंग के अनुसार गरीबी से जीवन के कई पहलू प्रभावित होते है। मंहगाई के कारण मकानों के मूल्य बढे, गरीब अश्वेत परिवार उन बस्तियों में नहीं रह सके, जहां शिक्षा व अन्य सामाजिक सुविधाएं बेहतर थी। हार्वर्ड विश्वविधालय के समाजशास्त्री विलियम जूलियस विलसन के अनुसार 1960 के बाद अश्वेतों में बेरोजगारी और विवाह के बिना बच्चे पैदा करने की दर बढी।

मौजूदा पीढी भी मुश्किल में है-

अमेरिका में अश्वेतों और मूल निवासियों का गरीबी में जीवन बिताना सामान्य बात है। 1983 से 2000 के बीच जन्में केवल 6 प्रतिशत श्वेत बच्चों ने अपना बचपन ऐसे इलाकों में गुजारा, जहां गरीबी की दर 20 प्रतिशत से कम है। पिस्टन विश्वविधालय के समाजशास्त्री पेट्रिक शार्को के अनुसार अश्वेत बच्चों का यह आंकलन 66 प्रतिशत है और मौजूदा पीढी भी इसी दौर से गुजर रही है। 26 प्रतिशत अश्वेत बच्चे ऐसी बस्तियों में रहते है, जहां गरीबी की दर 30 प्रतिशत से अधिक है और 70 प्रतिशत अश्वेत परिवार घटिया किस्म के मकानों में रहते है, जबकि श्वेत बच्चे केवल 4 प्रतिशत ही इस श्रेणी में आते है।



शिक्षा में असमानता—

1960 के दशक में अश्वेत छात्रों को श्वेत बस्तियों की स्कूलों में लाने की पहल चालू की गई। 1970 के मध्य तक यह प्रयास श्वेत अभिभावकों के विरोध की वजह से खत्म हुए। 1980 के बाद से स्कूलों में रंग के आधार पर विभाजन की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री रकर जॉनसन ने एक अध्ययन के अनुसार यह बताया कि स्कूलों में श्वेत छात्रों के साथ पढ़ने वाले अश्वेत छात्रों के जेल जाने की दर 22 प्रतिशत कम रही। उनकी आय भी 30 प्रतिशत बढ़ी। 2016 में 25 साल से अधिक आयु के 29 प्रतिशत अश्वेतों के पास डिग्री थी, जबकि श्वेत वर्ग के 44 प्रतिशत की पास डिग्री थी। कई मामलों में अधिकतर अश्वेतों की स्थिति आज भी 50 साल पहले जैसी ही है।

अमेरिका में श्वेत-अश्वेतों की स्थिति में अन्तर को दर्शाते ये आकड़ें

वर्ग	बेरोजगारी दर	संपत्ति	घरेलू आय
श्वेत	14.2	176000 \$	71000 \$
अश्वेत	16.7	171000 \$	41000 \$

अमेरिका में अश्वेत बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय और संपत्ति, शिक्षा एवं जीवन स्तर के आधार पर श्वेतों की तुलना में आज भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी औसत घरेलू आय लगभग 40 प्रतिशत कम है अश्वेतों की घरेलू औसत आय लगभग 13 लाख प्रति वर्ष है, वहीं श्वेतों की आय 53.65 लाख प्रतिवर्ष है। ऐसे में अमेरिकी श्रम विभाग की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर श्वेतों में 14.2 और अश्वेतों में 16.7 अर्थात् (श्वेतों की तुलना में 2.5 प्रतिशत ज्यादा है), घरेलू आय की स्थिति में अश्वेतों के



पास औसतन 41 हजार डॉलर और श्वेतों के पास 71 हजार डॉलर है। संपत्ति के आंकड़ों में अश्वेतों के पास 176 हजार डॉलर और श्वेतों के पास 171 हजार डॉलर है। श्वेतों के पास औसत संपत्ति लगभग 15 गुना अधिक है। संसद ब्यूरो ऑफ अमेरिका द्वारा 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 तक अमेरिका के कुल व्यापार में अफ्रीकन-अमेरिकियों की 9 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। अमेरिका में कई नामी कंपनियों जैसे विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, एसीटी-फर्स्ट गुप्स, ब्रीज वाटर इंटीरियर्स, एलएलसी, कोका-कोला, बेवरेज, और द बॉटम लाइन जैसी विश्व स्तरीय कंपनियों के मालिक अफ्रीकी- अमेरिकन लोग हैं।

स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्तर

अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विस ऑफ माइनोरिटी हैल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में अश्वेत व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा लगभग 76.1 वर्ष , जबकि श्वेतों में यह आंकड़ा 79.8 वर्ष है। अफ्रीकी-अमेरिकियों में मृत्यु दर श्वेतों की तुलना में अधिक है। इसमें हृदय रोग से जुड़ी बीमारियां कैंसर, अस्थमा, इन्फ्लूएंजा, डाइबिटीज, एचआईवी एड्स और हत्याएं शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय जगत पर प्रभाव- अमेरिका में नस्लीय हिंसा और पुलिस बर्बरता पर फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, सहित 14 से अधिक देशों में लोग प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जुटे। अमेरिका के सभी प्रांतों के अलावा जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और प्रोटरिया में हजारों लोग विरोध जताने सड़कों पर उतरें। जर्मनी में 15 हजार लोगों ने रैली निकाली। नीदरलैंड्स में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ। कनाडा में दो हफ्ते तक रंगभेद और पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। यूरोप,



अफ्रीका में भी प्रदर्शन हुए। ब्रिटेन के सेंट्रल लंदन वेस्टमिंस्टर में भी प्रदर्शन हुए। विश्वस्तरीय दबाव के कारण अमेरिकन प्रशासन के हालात इतने खराब हो गए कि राष्ट्रपति ट्रंप को सेना के 1600 जवान तैनात करने पड़े। ट्रंप ने दावा किया कि मेरी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बाद अश्वेत समुदाय के लिए सबसे अधिक काम किया। अश्वेतों के कॉलेजों के लिए फंड की गारंटी दी, क्रिमिनल जस्टिस रिफार्म एक्ट द्वारा देश में बेरोजगारी, गरीबी एवं अपराध की दर सबसे कम रही। स्टैटिस्टिका के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में पुलिस द्वारा फायरिंग में मारे गए कुल लोगों में 24 प्रतिशत अफ्रीकी अमेरिकी थे।

सारांश—अमेरिका को विश्व महाशक्ति के रूप में अपनी छवि बनाएं रखने के लिए काले-गोरे के भेद को समाप्त करना होगा। अश्वेतों की शिक्षा और सामाजिक हितों के लिए कार्य कर रही संस्था **नॉर्थसाइड अचिवमेंट जोन** चलाने वाली सॉन्ट्रा कहती है— स्वस्थ समाज बनाने के लिए अश्वेत अमेरिकी जागरूक होकर आज अपनी क्षमताएं पहचान चुके हैं। आजादी और न्याय के वादे आज भी पूरे नहीं हुए हैं। न्याय समानता और मानवतावाद की चिंता के बजाय आज भी श्वेत समाज का एक बड़ा वर्ग यथास्थिति को बनाये रखना चाहता है। स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए पुलिस तंत्र को हटाने, समाप्त करने के बजाय सुधारना आवश्यक है ताकि टिकाऊ कानून व्यवस्था देने के लिए कानून के प्रति सम्मान का भाव जगाया जा सके। बाइडेन यदि राष्ट्रपति चुनाव जितना चाहते हैं तो उन्हें मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे हिंसा और पुलिसिंग को गंभीर चुनौती के रूप में लेंगे। महामारी के बाद बढ़ती बेरोजगारी, हतोत्साहित पुलिस बल के कारण हिंसा, गोलीबारी की वारदातें देश में बढ़ रही हैं पिछले कुछ समय से विभिन्न कारणों से पहले ही 100 पुलिस अधिकारी हट चुके हैं, कुछ ने इस्तीफा दे दिया, कुछ को निकाल दिया गया तो



कुछ जार्ज फ्लॉयड मामले से उत्पन्न तनाव के कारण नौकरी छोड चुके है। इस साल के लिए 888 पुलिस कर्मियों के बजट से भी कम पुलिस तंत्र मिनियापोलिस में बच सकता है। अब तक पुलिस विभाग को समाप्त कर उसके स्थान पर सामुदायिक सुरक्षा और हिंसा रोकथाम विभाग बनाने का समर्थन कर रहे लोग अब ये मान चुके है कि पुलिस तंत्र को समाप्त करने से समुदाय की सुरक्षा खतरे में पड जायेगी। अतः सिटी काउंसिल भी पुलिस अधिकारियों की उचित संख्या को बनाये रखना चाहती है ताकि जार्ज फ्लॉयड की मौत से भडकी हिंसा से अर्थव्यवस्था और व्यापार को हुए नुकसान को रोका जा सके। ऐसे में पुलिस तंत्र को समाप्त करने से स्थितियां और ज्यादा विकट हो जायेगी, अतः सुधार पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। आज दुनिया में धार्मिक-जातीय असहिष्णुता जनित भेदभाव और रंगभेद आधारित हिंसा से गुजर रहे अमेरिका में मौजूदा उथल पुथल से उबारने के लिए मार्टिन लूथर किंग की पुनः जरूरत अनुभव हो रही है।



संदर्भ ग्रंथ—

अमेरिका का इतिहास—हेनरी बेमफोर्ड पार्कस(अनुवादक: विश्व प्रकाश गुप्त)
खोसला पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय राजनीति—डा. बी एल फडिया, कुलदीप फडिया, साहित्य भवन
पब्लिकेशन

अंतरराष्ट्रीय विधि—डा. श्याम किशोर कपूर, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

विश्व के प्रमुख संविधान—डा. प्रभुदत्त शर्मा, कालेज बुक डिपो, जयपुर

नई सहस्राब्दी का आंतकवाद: सधर्ष के बदलते प्रतिमान— डा. वीरेन्द्र सिंह
यादव, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय राजनीति—चन्द्रशेखर सूद, निरंजन बहुगुणा, राधा पब्लिकेशन, नई
दिल्ली

पत्र, पत्रिकाएं, प्रतिवेदन